[2010] 13 (एडीडीएल.) एस. सी. आर 851

नाहर सिंह यादव और अन्य

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

(2008 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 12981)

19 नवंबर, 2010

[डी. के. जैन, वी. एस. सिरपुरकर और जी. एस. सिंघवी, जे. जे.]

1. केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में "सीबीआई"), भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, गाजियाबाद द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपने हलफनामे में हमारे विचार के लिए उठाया गया संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या दायर आरोप पत्र से उत्पन्न मुकदमा चल रहा है या नहीं? केस आरसी-1(ए)/2008/सीबीआई/एसीबी/गाजियाबाद में सीबीआई और केस अपराध संख्या 152/2008 पीएस कवि नगर, गाजियाबाद में स्थानीय पुलिस, गाजियाबाद विशेष न्यायाधीश, सीबीआई की अदालत से स्थानांतरित होने के योग्य है। गाजियाबाद को किसी अन्य सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत में, अधिमानतः दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत, ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि वह मामले की सुनवाई

दिन-प्रतिदिन के आधार पर करे और इसे दो साल की अवधि के भीतर पूरा करे।

2. चूंकि यह मामला, जिसे आम तौर पर "गाजियाबाद पी.एफ. घोटाला" के नाम से जाना जाता है, उपरोक्त प्रार्थना को जन्म देता है, इसमें न्यायिक व्यवहार के मानकों का उल्लंघन शामिल है, जो उच्चतम स्तर का होने की उम्मीद है, चाहे वह हो या बाहर। बेंच, हम कथित घटनाओं से चिंतित हैं और उठाए गए मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। विवाद की सराहना करने के लिए, कुछ भौतिक तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है। ये हैं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सतर्कता विभाग के निष्कर्षों और उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्राधिकरण के अनुसरण में, धारा 409, 420, 467, 468, 471 के तहत मामला अपराध संख्या 152/2008, भारतीय दंड संहिता, 1860 की 477-ए, 120-बी (संक्षेप में "आईपीसी") और धारा 8, 9, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण की धारा 13(1)(डी) और 14 के साथ पठित श्रीमती की लिखित शिकायत पर थाना कवि नगर, गाजियाबाद में अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "अधिनियम") पंजीकृत किया गया था। रमा जैन, विशेष न्यायाधीश और सतर्कता अधिकारी, जिला न्यायालय, गाजियाबाद ने 15 फरवरी 2008 को एक दिवंगत आशुतोष अस्थाना, तत्कालीन केंद्रीय नाजिर, जिला न्यायालय, गाजियाबाद और 82 अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ, जिसमें 13 तृतीय श्रेणी कर्मचारी, 30 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल थे। जिला न्यायालय, गाजियाबाद और 39 बाहरी

लोग। यह आरोप लगाया गया था कि दिवंगत आशुतोष अस्थाना ने एफआईआर में नामित अन्य आरोपियों के साथ मिलकर जिला न्यायालय, गाजियाबाद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जीपीएफ के नाम पर धोखाधड़ी से बड़ी रकम निकाली।

इसके बाद, वर्तमान विशेष अनुमति याचिका 2008 के केस अपराध संख्या 152, पीएस कवि नगर, गाजियाबाद की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने के अनुरोध के साथ दायर की गई थी। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार ने उपरोक्त उल्लिखित मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (संक्षेप में "डीएसपीई अधिनियम") की धारा 6 के तहत 10 सितंबर 2008 को एक अधिसूचना जारी की। जिसे विचारार्थ इस न्यायालय के समक्ष भी रखा गया था। 23 सितंबर 2008 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ उक्त मामले की जांच को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया, यह देखते हुए कि "यह स्पष्ट किया गया है कि हालांकि हमने मामलों को तीन महीने के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है, लेकिन सीबीआई स्वतंत्र होगी। अंतिम रिपोर्ट या आरोपपत्र, जैसा भी मामला हो, पहले के समय में दाखिल करें और उसके बाद कानून के अनुसार आगे बढ़ें। जिस अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट या आरोपपत्र दायर किया गया है, वह मामला, जैसा भी हो, रिपोर्ट या आरोपपत्र से निपटेगा। जैसा कानून में अपेक्षित हो वैसा हो।" इस न्यायालय के उपरोक्त

आदेश के मद्देनजर, तत्काल मामला भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, सीबीआई, गाजियाबाद द्वारा 1 अक्टूबर 2008 को दिवंगत आशुतोष अस्थाना और 82 अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ केस आरसी के रूप में 1(ए)/2008/सीबीआई/एसीबी/गाजियाबाद दर्ज किया गया था।

3. सीबीआई ने समय-समय पर जांच में हुई प्रगति के संबंध में इस न्यायालय में आवधिक स्थिति रिपोर्ट दायर की। अंततः, 30 जुलाई 2010 को सीबीआई द्वारा अंतिम रिपोर्ट दायर की गई। अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, जांच से पता चला कि 2001- 2008 की अवधि के दौरान, स्वर्गीय आशुतोष अस्थाना, बिल क्लर्क और सेंट्रल नाजिर, जिला न्यायालय, गाजियाबाद के रूप में काम करते हुए, लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके, जिला न्यायालयों, गाजियाबाद/यूपी सरकार को धोखा देने के इरादे से 6 जिला न्यायाधीशों/प्रभारी जिला न्यायाधीश और 71 अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश रची, धोखाधड़ी और बेईमानी से जिले से 6 करोड़ से अधिक की रकम निकाल ली। जीपीएफ निकासी के रूप में कोषागार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जीपीएफ के नाम पर पैसे निकालने के लिए फर्जी/जाली दस्तावेज तैयार कर उन्हें वास्तविक के रूप में उपयोग किया गया, जिससे सरकारी खजाने को `6 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ और खुद को लाभ हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, नामित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 467, 468

और 471 और अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आरोपपत्र, 3 जुलाई 2010 को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, गाजियाबाद की अदालत में दायर किया गया है।

4. सीबीआई द्वारा दायर विचाराधीन हलफनामे में, यह कहा गया है कि निम्नलिखित कारणों से मामले की सुनवाई को यूपी राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान, अधिमानतः दिल्ली में स्थानांतरित करने की तत्काल आवश्यकता है:

(i) गाजियाबाद के 6 पूर्व जिला न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, जिनमें से 3 को बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और जिला न्यायालय, गाजियाबाद के 48 तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। ये सभी व्यक्ति और उनके करीबी सहयोगी कई वर्षों से जिला न्यायालय, गाजियाबाद में काम कर रहे हैं और विभिन्न न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के साथ उनके करीबी संपर्क हैं, जो गाजियाबाद और यूपी के अन्य जिलों में तैनात रहे;

(ii) विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, जिनकी अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया है, ने अतीत में कुछ आरोपपत्रित न्यायिक अधिकारियों के साथ/उनके अधीन भी काम किया था;

(iii) श्रीमती. रमा जैन, पूर्व विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, गाजियाबाद इस मामले में शिकायतकर्ता हैं और वर्तमान में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जिला फर्रुखाबाद, यूपी के रूप में कार्यरत हैं;

(iv) 13 न्यायिक अधिकारियों और जिला न्यायालय, गाजियाबाद के 25 से अधिक कर्मचारियों को मामले में अभियोजन गवाह के रूप में उद्धृत किया गया है, जिनकी गवाही आरोपपत्रित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामले स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

(v) विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, गाजियाबाद की अदालत पर पहले से ही संवेदनशील निठारी हत्याकांड सहित लगभग 175 मामलों की सुनवाई का बोझ है, जिनकी सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जा रही है।

5. इसके बाद, सीबीआई द्वारा एक और हलफनामा दायर किया गया, जिसमें बाद के कुछ घटनाक्रमों की ओर इशारा करते हुए मुकदमे को गाजियाबाद से स्थानांतरित करने की मांग की गई।

6. 4 अगस्त 2010 के आदेश के तहत, आरोपपत्र में नामित सभी आरोपियों को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न मुकदमे को गाजियाबाद में विशेष न्यायाधीश, सीबीआई की अदालत से किसी अन्य सक्षम अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाए, अधिमानतः के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार. जवाब में आरोपी नंबर

1,4,5,6,8,15,19,20,55 और कुछ अन्य आरोपियों की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया है. सभी नामित अभियुक्तों ने विभिन्न आधारों पर मुकदमे को गाजियाबाद से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने पर आपत्ति जताई है।

7. हमने सीबीआई की ओर से उपस्थित विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री जी.ई. वाहनवती और आपत्तिकर्ताओं - कुछ हद तक आरोपी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है।

8. श्री जी.ई. विद्वान अटॉर्नी जनरल वाहनवती ने प्रस्तुत किया कि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नामित आरोपियों में से कुछ पूर्व न्यायाधीश/प्रशासनिक हैं। न्यायाधीशों, बड़े पैमाने पर जनता के मन में यह उचित आशंका होगी कि ट्रायल न्यायाधीश, उनके पूर्व सहयोगी होने के नाते, आरोपी के पक्ष में पक्षपाती हो सकते हैं और इसलिए, मामले की विशिष्ट परिस्थितियाँ न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक बनाती हैं। मुकदमे को किसी तटस्थ स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। विद्वान वकील ने आगे कहा कि स्थानांतरण के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को सबसे महत्वपूर्ण विचार यह करना चाहिए कि न्यायपालिका में जनता का विश्वास बनाए रखा जाना चाहिए, और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए,

वर्तमान मामले में स्थानांतरण करना समीचीन होगा। मुकदमा दिल्ली में एक विशेष न्यायाधीश के पास।

9. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण (एसएलपी (सी) संख्या 12981/2008 में) ने तर्क दिया कि केवल आरोपी की असुविधा स्थानांतरण के लिए आवेदन को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती है, खासकर एक मामले में वर्तमान मामले की तरह, जहां एक गंभीर आशंका है कि अभियुक्तों, गवाहों और ट्रायल जज के बीच पिछले संबंधों के कारण मुकदमा स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो सकता है।

10. इसके विपरीत, कुछ अभियुक्तों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406(2) (संक्षेप में "सीआरपीसी") में प्रावधान है कि स्थानांतरण के लिए एक आवेदन केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। एक इच्छुक पार्टी द्वारा, और इसलिए, सीबीआई जो कि जांच एजेंसी है, को उक्त प्रावधान के अर्थ में एक इच्छुक पार्टी नहीं कहा जा सकता है और मुकदमे के हस्तांतरण के लिए इस तरह के आवेदन को स्थानांतरित करने का हकदार नहीं है। ए.आर. में इस न्यायालय के निर्णय की सराहना करते हुए। अंतुले बनाम. आर.एस. नायक एवं अन्य, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 4 के तहत विशेष न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की शक्ति विधायी प्रकृति की है, और इसलिए, सीआरपीसी की धारा 406 के तहत

एक आवेदन दायर किया जा सकता है। गलत धारणा है. अगला तर्क यह दिया गया कि नामित आरोपियों में से कोई भी न्यायिक पद पर नहीं है, और इसलिए, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वे गवाहों को प्रभावित करेंगे, खासकर जब 13 गवाह स्वयं न्यायिक अधिकारी हैं। यह तर्क दिया गया कि यदि स्थानांतरण का एकमात्र आधार यह तथ्य है कि गवाहों को कुछ अभियुक्तों की पिछली स्थिति के कारण प्रभावित किया जा सकता है, तो मुकदमे के स्थान का उस संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात पर जोर दिया गया कि मुकदमे के स्थानांतरण से आरोपी व्यक्तियों को बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि उन्हें खुद को लखनऊ या इलाहाबाद से बहुत दूर दिल्ली में स्थानांतरित करना होगा, जहां वे सेवानिवृत्ति के बाद रह रहे हैं और उनके बचाव के लिए नया वकील करना होगा।.

11.आरोपी बनाए गए 34 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की ओर से पेश विद्वान वकील विश्वजीत सिंह ने दलील दी कि मुकदमे के स्थानांतरण से आरोपियों को भारी कठिनाई होगी, जिन्हें न केवल लंबी दूरी की यात्रा करनी होगी, बल्कि व्यस्त भी रहना होगा। दिल्ली में महंगे वकील भी करने होगें। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि सीबीआई ने अपनी आशंका के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया है, विश्वसनीय सामग्री तो दूर की बात है कि अगर मुकदमा गाजियाबाद में हुआ तो न्याय का गर्भपात हो जाएगा।

12. मुख्य मुद्दे पर विचार करने से पहले, अर्थात। क्या मुकदमे को गाजियाबाद से स्थानांतरित करना वांछनीय होगा, हम मुकदमे के स्थानांतरण के लिए आवेदन को प्राथमिकता देने में सीबीआई के अधिकार क्षेत्र के बारे में कुछ आरोपियों की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति से निपटेंगे। तत्काल मामले को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दायर करने की सीबीआई की क्षमता के संबंध में आपत्तिकर्ताओं-अभियुक्त व्यक्तियों के तर्क की सराहना करने के लिए, डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 का उल्लेख करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:

> " शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए राज्य सरकार की सहमति। धारा 5 में निहित किसी भी बात को दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के किसी भी सदस्य को उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना राज्य के किसी भी क्षेत्र में शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में सक्षम नहीं माना जाएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश या रेलवे क्षेत्र नहीं है।"

13. यह स्पष्ट है कि डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के संचालन से, एक बार जब राज्य सरकार सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी करती है, तो सीबीआई राज्य पुलिस के समान शक्तियों का प्रयोग करने की हकदार है। जांच के

संबंध में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, सीबीआई की वर्तमान संरचना और स्थिति के आलोक में, यह स्पष्ट है कि सीबीआई उस विशेष मामले में अभियोजन एजेंसी की भूमिका निभाती है।

14.सीआरपीसी की धारा 406(2). यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय उप-धारा (1) के तहत शक्ति का प्रयोग केवल भारत के अटॉर्नी जनरल या किसी राज्य के महाधिवक्ता या इच्छुक पार्टी के आवेदन पर ही कर सकता है।

15. एक आपराधिक मुकदमा प्रासंगिक तथ्यों के उचित सबूत पर अपराधियों को दंडित करने के उद्देश्य से साक्ष्य की न्यायिक जांच है, मुख्य प्रश्न अभियुक्त का अपराध या निर्दोषता है। आपराधिक मुकदमे में अभियोजन एजेंसी को दी गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि सीआरपीसी की धारा 406(2) के प्रयोजनों के लिए सीबीआई एक इच्छुक पक्ष नहीं है।

16. हमारी राय है कि एक बार जब डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है, तो सीबीआई एक जांच एजेंसी की भूमिका निभाती है और जैसा कि ऊपर कहा गया है, सीबीआई को भी जांच एजेंसी की भूमिका सौंपी जाती है। उस विशेष मामले के संबंध में अभियोजन एजेंसी, और इसलिए, वह सीआरपीसी

की धारा 406(2) के तहत एक आवेदन दायर करने की हकदार है। तदनुसार, प्रारंभिक आपत्ति खारिज की जाती है।

17. मुख्य मुद्दे पर लौटते हुए, एक सच्ची और निष्पक्ष सुनवाई संविधान के अनुच्छेद 21 की शर्त है, जो घोषित करती है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके "जीवन" या "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" से वंचित नहीं किया जाएगा। . इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि एक आपराधिक मुकदमा, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को न केवल उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बल्कि उसके जीवन से भी वंचित किया जा सकता है, निष्पक्ष होना चाहिए और आरोपी के पक्ष या विपक्ष में कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। एक निष्पक्ष और अप्रभावित सुनवाई निष्पक्ष सुनवाई की मूलभूत आवश्यकता है, जो आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली की पहली और सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्यता है। यदि कोई आपराधिक मुकदमा स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, तो आपराधिक न्याय प्रणाली निस्संदेह खतरे में पड़ जाएगी, जिससे आम आदमी का सिस्टम में विश्वास कम हो जाएगा, जो बड़े पैमाने पर समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए, जब भी यह दिखाया जाए कि किसी विशेष मुकदमे की निष्पक्षता में जनता का विश्वास किसी भी कारण से गंभीर रूप से कम होने की संभावना है, सीआरपीसी की धारा 406। इस न्यायालय को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में या एक उच्च

न्यायालय के अधीनस्थ एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या बेहतर क्षेत्राधिकार वाले दूसरे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार देता है। हालाँकि, यह घिसा-पिटा कानून है कि सीआरपीसी की धारा 406 के तहत शक्ति प्रदान की जाती है। इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए और इसका प्रयोग संयमित ढंग से और बड़ी सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इस बात पर थोड़ा ज़ोर देने की ज़रूरत है कि स्थानांतरण के लिए प्रार्थना केवल तभी की जानी चाहिए जब यह अच्छी तरह से प्रमाणित आशंका हो कि न्याय निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण और बिना किसी पूर्वाग्रह के नहीं दिया जाएगा। इस तरह की आशंका को प्रदर्शित करने वाली किसी भी सामग्री के अभाव में, यह न्यायालय मुकदमे के स्थानांतरण के लिए आवेदन पर विचार नहीं करेगा, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में मुकदमे का स्थानांतरण न केवल संपूर्ण राज्य न्यायपालिका बल्कि अभियोजन एजेंसी की विश्वसनीयता को दर्शाता है। जिसमें सरकारी वकील भी शामिल होंगे।

18. जाहिरा हबीबुल्ला एच. शेख बनाम में। गुजरात राज्य और अन्य.2, "निष्पक्ष सुनवाई" अभिव्यक्ति के महत्व को समझाते हुए, इस न्यायालय ने कहा था कि:

> "निष्पक्ष सुनवाई का मतलब स्पष्ट रूप से एक निष्पक्ष न्यायाधीश, एक निष्पक्ष अभियोजक और न्यायिक शांति के

माहौल के समक्ष सुनवाई होगी। निष्पक्ष सुनवाई का मतलब एक ऐसा मुकदमा है जिसमें अभियुक्तों, गवाहों या जिस कारण पर मुकदमा चलाया जा रहा है उसके लिए या उसके खिलाफ पूर्वाग्रह या पक्षपात होता है। 2004) 4 एससीसी 158 को समाप्त कर दिया गया। यदि गवाहों को धमकी दी जाती है या उन्हें झूठे सबूत देने के लिए मजबूर किया जाता है, तो भी निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। महत्वपूर्ण गवाहों को सुनने में विफलता निश्चित रूप से निष्पक्ष सुनवाई से इनकार है।"

19. मेनका संजय गांधी और अन्य में। बनाम रानी जेठमलानी3, इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए, वी.आर. कृष्णा अय्यर, जे. ने कहा:

"निष्पक्ष सुनवाई का आश्वासन न्याय प्रदान करने की पहली अनिवार्यता है और स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव पेश करते समय अदालत के लिए विचार करने के लिए केंद्रीय मानदंड किसी पक्ष की अतिसंवेदनशीलता या सापेक्ष सुविधा या कानूनी सेवाओं की आसान उपलब्धता या मिनी की तरह नहीं है। -शिकायतें। यदि न्यायालय को स्थानांतरण की अपनी शक्ति का प्रयोग करना है तो सार्वजनिक न्याय और

उसके संबंधित वातावरण के दृष्टिकोण से कुछ अधिक ठोस, अधिक सम्मोहक, अधिक जोखिम भरा होना आवश्यक है। यह प्रमुख सिद्धांत है, हालांकि परिस्थितियाँ असंख्य हो सकती हैं और हर मामले में अलग-अलग होते हैं। हमें इस नियम को ध्यान में रखते हुए इस कसौटी पर याचिकाकर्ता के आधारों का परीक्षण करना होगा कि आम तौर पर शिकायतकर्ता को अधिकार क्षेत्र वाली किसी भी अदालत को चुनने का अधिकार है और आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि उसके खिलाफ मामला कहां चलाया जाना चाहिए। यहां तक कि इसलिए, न्याय की प्रक्रिया को पक्षों को परेशान नहीं करना चाहिए और उस दृष्टिकोण से अदालत परिस्थितियों का आकलन कर सकती है।"

20. अब्दुल नज़र मदनी बनाम में। टी.एन राज्य और Anr.4, एक समान आवेदन से निपटते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए थे:

"अनुमानों और अनुमानों के आधार पर निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच या सुनवाई नहीं होने की आशंका उचित होनी चाहिए न कि काल्पनिक। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि आपराधिक न्याय निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से और बिना

किसी पूर्वाग्रह के संभव नहीं है, तो किसी भी अदालत या यहां तक कि किसी भी स्थान पर, (1979) 4 एससीसी 167 (2000) 6 एससीसी 204 उपयुक्त अदालत मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित कर सकती है जहां उसे लगता है कि निष्पक्ष और उचित सुनवाई अनुकूल है। कोई भी सार्वभौमिक या कठोर और तेज़ नियम ऐसा नहीं कर सकता एक स्थानांतरण याचिका पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए जिसे हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। मुकदमे में पेश किए जाने वाले गवाहों सहित पक्षों की सुविधा भी स्थानांतरण याचिका पर निर्णय लेने के लिए एक प्रासंगिक विचार है। की सुविधा पार्टियों का मतलब जरूरी नहीं कि केवल याचिकाकर्ताओं की सुविधा हो, जिन्होंने आशंका की गलत धारणाओं पर अदालत का दरवाजा खटखटाया। स्थानांतरण के प्रयोजनों के लिए सुविधा का मतलब अभियोजन पक्ष, अन्य अभियुक्तों, गवाहों और समाज के व्यापक हित की सुविधा है।"

21. के. अनबझगन बनाम में। पुलिस अधीक्षक एवं अन्य 5, इस न्यायालय के पास मुख्य रूप से मुकदमे में राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका के आधार पर एक आपराधिक मुकदमे को तमिलनाडु से दूसरे

राज्य में स्थानांतरित करने की प्रार्थना से निपटने का अवसर था। अंततः मामले को कर्नाटक राज्य में स्थानांतरित करने का निर्देश देते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

> "स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई संविधान के अनुच्छेद 21 की अनिवार्य शर्त है। यह घिसा-पिटा कानून है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। यदि आपराधिक मुकदमा स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है और इससे मुक्त नहीं है पूर्वाग्रह, न्यायिक निष्पक्षता और आपराधिक न्याय प्रणाली खतरे में पड़ जाएगी, जिससे व्यवस्था में जनता का विश्वास डगमगा जाएगा और कानून के शासन पर संकट आ जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामले में सवाल यह नहीं है कि क्या याचिकाकर्ता वास्तव में है पक्षपातपूर्ण लेकिन सवाल यह है कि क्या परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि याचिकाकर्ता के मन में उचित आशंका है।"

22. हाल ही में कैप्टन अमरिन्दर सिंह बनाम. प्रकाश सिंह बादल और अन्य.6, सीआरपीसी की धारा 406 के तहत दो स्थानांतरण आवेदनों से निपटते समय। इस आधार पर कि राज्य सरकार में बदलाव के साथ, नए मुख्यमंत्री के प्रभाव के साथ-साथ तीन-न्यायाधीशों की पीठ के लिए

बोल रहे लोक अभियोजक, पी. सदाशिवम, जे. द्वारा रुचि की कमी के कारण मुकदमे को झटका लग रहा था। इस प्रकार देखा गया है:

> " किसी आपराधिक मामले के स्थानांतरण के लिए, मामले के पक्ष की ओर से यह उचित आशंका होनी चाहिए कि न्याय नहीं किया जाएगा। यह न्याय प्रशासन के सिद्धांतों में से एक है कि न्याय केवल नहीं किया जाना चाहिए लेकिन इसे होते हुए देखा जाना चाहिए। दूसरी ओर, केवल यह आरोप कि यह आशंका है कि किसी मामले में न्याय नहीं होगा, पर्याप्त नहीं है। दूसरे शब्दों में, अदालत को यह भी देखना होगा कि कथित आशंका उचित है या नहीं या नहीं। आशंका पर न केवल विचार किया जाना चाहिए बल्कि अदालत को यह उचित आशंका प्रतीत होनी चाहिए।
>
> निष्पक्ष सुनवाई का आश्वासन न्याय प्रदान करने की पहली अनिवार्यता है। आपराधिक मुकदमे का उद्देश्य बाहरी विचारों से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष और निष्पक्ष न्याय प्रदान करना है। जब यह दिखाया जाता है कि मुकदमे की निष्पक्षता में जनता का विश्वास गंभीर रूप से कम हो जाएगा, तो पीड़ित पक्ष धारा 407 के तहत राज्य के भीतर

और धारा 406 सीआरपीसी के तहत देश में कहीं भी मामले को स्थानांतरित करने की मांग कर सकता है।

हालाँकि, निष्पक्ष और निष्पक्ष जाँच या सुनवाई न हो पाने की आशंका उचित होनी आवश्यक है न कि काल्पनिक। स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई संविधान के अनुच्छेद 21 की अनिवार्य शर्त है। यदि आपराधिक मुकदमा स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है और यदि यह पक्षपातपूर्ण है, तो न्यायिक निष्पक्षता और आपराधिक न्याय प्रणाली खतरे में पड़ जाएगी, जिससे प्रणाली में जनता का विश्वास डगमगा जाएगा यह आशंका अदालत को उचित प्रतीत होनी चाहिए।"।

23. आर. बालकृष्ण पिल्लई बनाम में। केरल राज्य7 ने स्थानांतरण के लिए एक प्रार्थना को खारिज कर दिया, जो इस आधार पर की गई थी कि अपील की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों में से एक पहले एक अन्य मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ कदाचार के आरोप की जांच करने वाले आयोग में एक वकील के रूप में पेश हुआ था, कोर्ट ने यह देखा था निम्नानुसार:

"उनके खिलाफ आरोप पूरी तरह से एक अलग मामले के लिए हैं जो एडामालयार परियोजना के सुधार कार्य से जुड़े

नहीं हैं। दूसरे, एक वकील के रूप में अभ्यास करते समय एक न्यायाधीश कई मामलों में उपस्थित हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसके पास कोई व्यक्तिगत मामला होगा। उक्त मामलों या उसमें शामिल व्यक्तियों के साथ रुचि या संबंध और उनके प्रति पक्षपातपूर्ण होगा। इसलिए, यह मानना या निष्कर्ष निकालना मुश्किल होगा कि विद्वान न्यायाधीश, एक अलग मामले में एक वकील के रूप में जांच आयोग की सहायता करने के कारण मामले में, याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह होगा और कानून के अनुसार न्याय नहीं दिया जाएगा। इस तरह के विवाद को स्वीकार करने से न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और कठोर चीजें गंभीर रूप से कमजोर हो जाएंगी।"

24.इस प्रकार, हालांकि सीआरपीसी की धारा 406 के तहत शक्ति है या नहीं, यह तय करने के लिए कोई कठोर और अनम्य नियम या परीक्षण निर्धारित नहीं किया जा सका। प्रयोग किया जाना चाहिए, उक्त धारा की उप-धाराओं (2) और (3) को पढ़ने और इस न्यायालय के निर्णयों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मुकदमे के हस्तांतरण का आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए नियमित मामला या (2000) 7 एससीसी 129 केवल इसलिए कि एक इच्छुक पक्ष ने परीक्षण के उचित संचालन के बारे में कुछ आशंका व्यक्त की है। इस शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक और

असाधारण स्थितियों में किया जाना चाहिए, जहां परीक्षण को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो जाता है। मुकदमे के स्थानांतरण के लिए आवेदन पर विचार करते समय कुछ व्यापक कारक जिन्हें ध्यान में रखा जा सकता है वे हैं: -

(i) जब ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य मशीनरी या अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के साथ मिलकर काम कर रहा है, और अभियोजन पक्ष के ढुलमुल रवैये के कारण न्याय में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है;

(ii) जब यह दिखाने के लिए सामग्री हो कि आरोपी अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित कर सकता है या शिकायतकर्ता को शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है;

(iii) आधिकारिक और गैर-आधिकारिक गवाहों की यात्रा और अन्य खर्चों का भुगतान करने में राज्य के खजाने द्वारा वहन किए जाने वाले बोझ के अलावा, आरोपी, शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष और गवाहों को होने वाली तुलनात्मक असुविधा और कठिनाइयाँ।

(iv) सांप्रदायिक रूप से तनावपूर्ण माहौल, जो लगाए गए आरोपों और अभियुक्तों द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति के कारण निष्पक्ष सुनवाई करने में असमर्थता के कुछ सबूत दर्शाता है; और

(v) कुछ सामग्री का अस्तित्व जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ व्यक्ति इतने शत्रुतापूर्ण हैं कि वे न्याय की प्रक्रिया में

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं या हस्तक्षेप करने की संभावना रखते हैं।

25.उपर्युक्त व्यापक मापदंडों की कसौटी पर दोनों पक्षों के प्रतिद्वंद्वी दावों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि सीबीआई ने इस आशंका पर विचार किया कि गाजियाबाद में मामले की सुनवाई निष्पक्ष नहीं हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप गर्भपात हो सकता है। न्याय गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से, हम पूर्वाग्रह की उचित आशंका का कोई निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हैं और न ही हम यह सोचते हैं कि यह आशंका एक बेबुनियाद आरोप पर आधारित है कि चूंकि ट्रायल जज और कुछ नामित आरोपी किसी समय करीबी सहयोगी थे। समय और यह कि कुछ गवाह न्यायिक अधिकारी हैं, गाजियाबाद में मुकदमा पक्षपातपूर्ण और निष्पक्ष नहीं होगा, जिससे व्यवस्था में जनता का विश्वास कम होगा। हालाँकि यह सच है कि न्यायाधीश इंसान हैं, स्वचालित नहीं, लेकिन एक न्यायिक अधिकारी के लिए, चाहे वह किसी भी क्षमता में कार्य कर रहा हो, यह अनिवार्य है कि उसे इस विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए कि उसे यह सुनिश्चित करने के अलावा किसी अन्य कारक द्वारा निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय देगा, जो उसके विवेक के अनुसार उसके सामने रखी गई सामग्री के आधार पर सही होगा। इस अनिवार्यता का कोई अपवाद नहीं है. इसलिए, हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि

गवाह या विशेष न्यायाधीश केवल इसलिए आरोपियों के पक्ष में प्रभावित हो जाएंगे क्योंकि उनमें से कुछ उनके पूर्व सहयोगी होंगे। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इस तरह के आरोप को बिना किसी ठोस बात के स्वीकार करना, किसी राज्य की संपूर्ण न्यायपालिका की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता को गंभीर रूप से कमजोर करता है। तदनुसार, हम मुकदमे को गाजियाबाद से स्थानांतरित करने की प्रार्थना के समर्थन में दिए गए इस आधार को सिरे से खारिज करते हैं।

26. जहां तक इस दलील का संबंध है कि विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, गाजियाबाद की अदालत पर पहले से ही अत्यधिक बोझ है, हमारी राय में, यह फिर से मुकदमे के हस्तांतरण का आधार नहीं है। यदि उक्त न्यायालय पर अत्यधिक बोझ है, तो यह उच्च न्यायालय के लिए खुला होगा कि वह राज्य सरकार से गाजियाबाद में एक विशेष न्यायाधीश का एक और न्यायालय बनाने का अनुरोध करे और हमें विश्वास है कि मामले की प्रकृति और गंभीर चिंता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पहले ही 10 सितंबर 2008 को अधिसूचना जारी करके तुरंत और शीघ्रता से दिखाया है, राज्य सरकार इस संबंध में उचित कदम उठाएगी ताकि न केवल इस मामले में बल्कि अन्य संवेदनशील परीक्षणों में भी दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके। उस न्यायालय में भी लंबित रहेगा।

27.उपर्युक्त कारणों से, वर्तमान में, हमें मुकदमे को गाजियाबाद से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के सीबीआई के अनुरोध में कोई योग्यता नहीं मिलती है। तदनुसार, प्रार्थना अस्वीकार की जाती है। ट्रायल कोर्ट को मामले पर तेजी से आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डॉ. महेंद्र कुमार गोयल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक एवं आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।